सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र के राज्यपाल

माननीय श्री. सी. पी. राधाकृष्णन

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

०९ दिसंबर २०२४

सम्मानीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं
राज्य विधानमंडल के सम्मानीय सदस्यगण,

१५ वीं राज्य विधानसभा के हाल ही में हुए आम चुनाओं के बाद राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों और मुख्यमंत्री और दोनों उप-मुख्यमंत्रियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।

२. मेरी सरकार, राज्य के लोगों की सेवा में राजमाता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेड़कर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज और कई अन्य महान नेताओं और समाज सुधारकों के उच्च आदर्शों का निरंतर अनुसरण करेगी।

३. मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, केंद्र सरकार ने हाल ही में मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। इससे ४५० विश्वविद्यालयों में मराठी भाषा के अध्ययन के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने में मदद मिलेगी। मराठी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार से अधिक धनराशि उपलब्ध होगी।

४. महाराष्ट्र यह, देश में एक अग्रणी औद्योगिक राज्य है। देश के कुल सकल घरेलु उत्पाद में महाराष्ट्र ने १४ प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है। राज्य को सीधे विदेशी निवेश करने के लिये पसंदीदा स्थान दिया जा रहा है।

वर्ष २०२३-२४ में महाराष्ट्र १,२५,१०१ करोड़ रुपयों के सीधे विदेशी निवेश से देश में अग्रणी रहा है। महाराष्ट्र ने, २०२४-२५ इस वर्ष के अप्रैल से सितंबर इस पहली दो तिमाहियों में १,१३,२३६ करोड़ रुपयों के सीधे विदेशी निवेश से फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्षों के सीधे विदेशी निवेश के ९० प्रतिशत से अधिक है।

५. मेरी सरकार ने, सन् २०२७-२८ तक एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र यह देश का पहला राज्य बनाने का बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

मेरी सरकार ने, प्रधान सेक्टर और उच्च प्रौद्योगिकी सेक्टर पर आधारित उत्पादन सेक्टर जैसे कि, सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहनों, अंतरिक्षयान और रक्षा, रसायन और पॉलिमर, लिथियम आयर्न बॅटरी, इस्पात और अन्य उत्पादों के अतिविशाल विनिर्माण परियोजनाओं को प्रणेता उद्योग का दर्जा देने और राज्य में अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हे विशेष प्रोत्साहन देने की नीति घोषित की है। उक्त नीति के तहत् पिछले आठ महीनों में राज्य की मंजूर परियोजनाओं में से लगभग ३,२९,००० करोड़ रुपयों का कुल निवेश आकर्षित होगा और १,१८,००० प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होंगे।

६. मेरी सरकार ने, राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा नीति, २०२३ और हरित डेटा सेंटर नीति भी घोषित की है। इस नीति का लक्ष्य मुंबई को भारत की डेटा सेंटर राजधानी बनाना है। इस नीति के एक भाग के रूप में, मुंबई और नवी मुंबई क्षेत्रों में हरित एकीकृत डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जायेगा जिससे राज्य में लगभग एक लाख करोड़ रुपयों से अधिक रुपयों का निवेश होगा और २०,००० रोजगार निर्माण होंगे।

७. मेरी सरकार ने, युवाओं में कौशल को बढ़ावा देने और उद्योंगों को कुशल श्रमशक्ति देने के लिए राज्य में, "मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना" शुरू की है। इस योजना के तहत्, १,१९,७०० उम्मीदवारोंने प्रशिक्षण में भाग लिया।

८. युवाओं को रोजगारक्षम बनाने के उद्देश्य से उन्हे प्रशिक्षण देने के लिए महाविद्यालयों में १००० आचार्य़ चाणक्य कौशल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों में हर वर्ष १,५०,००० युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

९. मेरी सरकार ने, महिला नवोद्योजकों को उनके कारोबार के शुरआती चरण में, २५ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के लिए "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला नवोद्योग योजना" शुरू की है।

१०. मेरी सरकार ने, युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए १,५३,००० रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आज तक ७८,३०९ पद भरे जा चुके है।

११. मेरी सरकार ने, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन अनुसूचित क्षेत्रों में (पेसा) १७ संवर्गों में ६,९३१ रिक्त पदों को मानदेय आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू की है।

१२. मेरी सरकार ने, राज्य में २१ से ६५ वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" कार्यान्वित की है। इस योजना के तहत् २ करोड़ ३४ लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं को प्रति महीना १,५०० रुपयों की राशि दी जा रही है और जुलाई महीने से नवंबर २०२४ तक पाँच महीने की किश्तें दी गई हैं। यह योजना आगे जारी रहेगी।

१३. सरकार ने, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए "चौथे महिला धोरण-२०२४" जारी किया है।

१४. मेरी सरकार, धुआँ रहित वातावरण में रहने के लिए पात्र लाभार्थियों को वर्ष में ३ गॅस सिलेंडर का पुनर्भरण निःशुल्क देने के लिए "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" कार्यान्वित कर रही है।

१५. मेरी सरकार ने, फ़रवरी, २०२४ महीने में जर्मनी के बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्य के साथ १०,००० कुशल श्रमशक्ति की आपूर्ति करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

१६. मेरी सरकार ने, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना के अंतर्गत आनेवाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की परिशोधित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना के साथ-साथ केंद्र सरकार की एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

१७. मेरी सरकार ने, सन् २०१४ से "प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण" के तहत् १९,५५,५४८ मकानों को मंजूरी दी हैं और उसमें से १२,६३,०६७ मकान संनिर्मित किये गये हैं।

मेरी सरकार ने, जुलाई २०२२ से अब तक राज्य प्रायोजित सभी आवास योजनाओं के तहत् ७,०७,४९६ मकानों को मंजूरी दी है और उसमें से ३,६३,१५४ मकानों को संनिर्मित किया गया हैं।

१८. मेरी सरकार ने, जिन ग्रामपंचायत में ग्रामपंचायत भवन नहीं है, ऐसी २,७८६ ग्राम पंचायतों को "बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना" के तहत् ग्रामपंचायत भवनों के संनिर्माण करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है।

१९. मेरी सरकार, राज्य के ४०९ शहरों में "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत् ३,८२,२०० मकानों के संनिर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने ४,१५० करोड़ रुपये दिये हैं और राज्य सरकार ने ४,४७५ करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

२०. सिडको आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समुह के लोगों के लिए किफ़ायती दरों में ६७,००० मकानों की महाआवास योजना कार्यान्वित कर रही है।

२१. मेरी सरकार ने, लोकनिर्माण कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत् ७४८० किलो मीटर लम्बाई की सड़कों के सिमेंट काँक्रीटीकरण करने का निर्णय लिया है।

२२. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य मुलभूत सुविधा विकास निगम के ज़रिये पुणे से छत्रपति संभाजी नगर तक एक नया छह लेन का हरितक्षेत्र द्रुतगती मार्ग विकसित करने के लिए मंजूरी दी है।

२३. मुंबई और पुणे के यात्रियों को निर्बाध और वातानुकूलित यात्री परिवहन सेवा देने के उद्देश्य से, मेरी सरकार ने, हाल ही में मुंबई में वांद्रे कुर्ला संकुल से आरे तक और पुणे में जिला न्यायालय, पुणे से स्वारगेट तक मेट्रो मार्ग को सार्वजनिक सेवा के लिए खुले किए गये हैं।

२४. मेरी सरकार ने, पुणे मेट्रो रेल चरण-२ के तहत् पुणे के विभिन्न भागों में कुल ४४ किलोमीटर लम्बाई के नवीन चार मेट्रो मार्गों का संनिर्माण करने का भी निर्णय लिया है।

२५. मेरी सरकार, भारत सरकार के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पालघर जिले के वाढ़वण बंदर को विकसित कर रही है। इस परियोजना की कुल लागत ७६,२२० करोड़ रुपये हैं।

२६. सरकार ने, निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ ४२५९ करोड़ रुपयों के निवेश से पालघर जिले के मुरबे में "बंदर क्षेत्र मेगा प्रकल्प" के संनिर्माण को मंजूरी दी है। इससे, स्थानीय उद्योगों को मदद मिलेगी और लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

२७. मेरी सरकार ने, पिछले दो वर्षों में २५ लाख २१ हजार हेक्टर सिंचाई क्षमता होनेवाली १६७ सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी है।

२८. सरकार ने, वैनगंगा-नळगंगा, नार-पार-गिरणा, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी और दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी इन चार नदी जोड़ योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी है। इससे, ४ लाख ३३ हजार हेक्टर सिंचाई क्षमता निर्माण होगी।

२९. मेरी सरकार, राज्य में "जल जीवन मिशन योजना" को सक्रियता से कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत् सरकार ने, ग्रामीण क्षेत्रों में १ करोड़ २७ लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिये है।

३०. मेरी सरकार ने, विदर्भ और मराठवाडा क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये "दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२" कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध होंगे।

३१. मेरी सरकार ने, किसानों को टिकाऊ सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई सुविधा देने के लिए "मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना" शुरू की है। "प्रधानमंत्री कुसुम" घटक-ब योजना के तहत् कुल ४ लाख ५ हजार सौर पंप बिठाने के लिये मंजूरी दी गई है। अब तक, संपूर्ण राज्य में १ लाख ८३ हजार सौर कृषि पंप बिठाये गये हैं।

३२. मेरी सरकार ने, कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली आपूर्ति करने के लिये "मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०" शुरू की है। इस योजना के तहत् लगभग ३५,००० एकड़ सरकारी और निज़ी भूमि पर १६,००० मेगावॉट क्षमतावाली सोलर विद्युत परियोजनाओं को जून २०२६ तक स्थापित किया जायेगा।

३३. सरकार ने, राज्य में ७.५ अश्वशक्ति तक के कृषि पंप उपभोक्ताओं को मुफ़्त बिजली देने के लिए "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, २०२४" शुरू की है। जिससे ४६ लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है।

३४. मेरी सरकार, राज्य में "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पाणलोट क्षेत्र विकास घटक २.० योजना" कार्यान्वित कर रही है, जिसमें ५ लाख ६५ हजार हेक्टर क्षेत्र शामिल होगा और इसकी कुल लागत १,३३५ करोड़ रुपये है।

३५. महाराष्ट्र धारित भूमि के विखंड़न की रोकथाम और समेकन करने संबंधी अधिनियम के उल्लघन में किसी भी गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये किये गये भूमि के विखंड़न के अंतरण के नियमितीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये मेरी सरकार ने, अधिनियम में यथोचित संशोधन द्वारा नियमितीकरण अधिमूल्य, भूमि के बाजार मूल्य के २५ प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत तक कम किया है।

३६. मेरी सरकार ने, राज्य में खरीप मौसम २०२३ के लिए कपास और सोयाबीन उत्पादक किसानों को वित्तीय सहायता दी है। तद्नुसार, ६७ लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में २,५०० करोड़ रुपयों से अधिक राशि जमा की गई है।

३७. मेरी सरकार ने, "प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना" के तहत् पात्र किसानों को "नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना" के तहत् सन् २०२३-२०२४ और सन् २०२४-२०२५ में नवम्बर २०२४ तक ९१ लाख से अधिक किसान परिवारों के खाते में सीधे लाभ अंतरण के ज़रिए ८,८९२ करोड़ रुपयों की राशि जमा की है।

३८. सरकार ने, व्यापक फसल बीमा योजना के तहत् खरीफ मौसम २०२३ के दौरान १ करोड़ १४ लाख किसानों को ७,४६६ करोड़ रुपयों का मुआवजा दिया है। सन् २०२३-२४ के रब्बी मौसम में ७१ लाख से अधिक किसानों ने इसमें भाग लिया और ४९ लाख हेक्टर से अधिक भूमि का बीमा किया गया है।

३९. मेरी सरकार, केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत् कुल ४,१४७ लाभार्थियों को लाभ दिया गया है।

४०. मछुआरों और उनके परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिये, उनके कल्याण और विकास करने के लिए मेरी सरकार ने, 'महाराष्ट्र भुजलाशिय मछुआरा कल्याण निगम' और 'महाराष्ट्र समुद्री मछुआरा कल्याण निगम' की स्थापना की है।

४१. मेरी सरकार ने, २६१ लिफ़्ट सिंचाई सहकारी संस्थाओं के लगभग १३२ करोड़ रुपयों के विलंबित मूल ऋण को माफ़ करने और संबंधित बैंकों को उक्त राशि अदा करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य में लिफ़्ट सिंचाई सहकारी संस्थाओं के कुल ४२,८४२ सदस्य किसान लाभान्वित होंगे।

४२. मेरी सरकार ने, सन् २०२४ के काजू मौसम के लिए राज्य के काजू उत्पादक किसानों को प्रति किलो काजू बीज पर १० रुपये की दर से आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। सरकार ने, इस योजना के लिए २७९ करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। इससे कोंकण क्षेत्र के १ लाख ३९ हजार किसानों को लाभ मिलेगा।

४३. केंद्र सरकार ने, सन् २०२४-२०२५ के मौसम में सोयाबीन के लिये ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में प्रति क्विंटल २९२ रुपयों से अधिक है। मेरी सरकार ने, ५४८ खरीद केंद्रों के ज़रिये खरीद प्रक्रिया शुरू की है और अब तक, १०,२०,२९६ क्विंटल सोयाबीन की खरीद की जा चुकी है। यह खरीद १२ जनवरी २०२५ तक जारी रहेगी।

४४. मेरी सरकार ने, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की हानी हुए ४० लाख ३३ हजार लाभार्थी किसानों के आधार संलग्न बैंक खातों में सीधे लाभार्थी प्रणाली के ज़रिए ३,७८७ करोड़ रुपयों की राशि वितरित की है।

४५. धान और मोटे अनाज़ की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद योजना के तहत् मेरी सरकार, खरीप विपणन मौसम २०२४-२५ के दौरान राज्य के किसानों से १३ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन धान और ७५ हजार मेट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद करेगी।

४६. मेरी सरकार ने, स्थायी रूप से बिना अनुदानित, बिना अनुदानित विशेष विद्यालयों, संलग्न छात्रावासों, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों साथ ही साथ अनाथ मतिमंद बालगृहों को सहायता अनुदान देने के लिए नीति तैयार की है।

४७. मेरी सरकार ने, ८ लाख रुपयों से कम वार्षिक पारिवारीक आय होनेवाली और शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ से सरकारी अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा लेनेवाली महिला छात्राओं को शैक्षणिक फीस और परीक्षा फीस माफ करने के लिए "राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना" शुरू की है। इस योजना के तहत् दो लाख से अधिक महिला छात्राओं को लाभ होगा।

४८. मेरी सरकार ने, राज्य में २५० आश्रम विद्यालयों को आदर्श आश्रम विद्यालयों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत् इन आश्रम विद्यालयों में डिजीटल कक्षा, आभासी कक्षा, टॅब प्रयोगशाला, चेहरा पहचान प्रणाली स्थापित की जायेगी।

४९. सरकार ने, विद्यालयों में बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकारी आश्रम विद्यालयों में बालसंरक्षण प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार, अध्यापकों और छात्रों को आवश्यक प्रशिक्षण देगी, जिससे आश्रम विद्यालयों में छात्र सहज़ता महसूस करें और भय तथा चिंता से मुक्त रहे।

५०. मेरी सरकार, राज्य के लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत्, सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ़्त इलाज दे रही है।

५१. मेरी सरकार ने, मुंबई, नासिक, ठाणे, जालना, हिंगोली, वाशिम, बुलढ़ाणा, अमरावती, भंडारा और गढ़चिरोली में नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। तदनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ के लिए एम. बी. बी. एस. के ९०० छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

५२. मेरी सरकार ने, कोल्हापुर और बुलढ़ाणा जिले में नए सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय और अस्पताल, रायगड़ जिले में सरकारी युनानी महाविद्यालय और अस्पताल, कोल्हापुर जिले में सरकारी होमिओपॅथी महाविद्यालय और अस्पताल तथा सरकारी योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है।

५३. मेरी सरकार ने, पॅरीस ऑलिम्पिक २०२४ में पदक विजेता ॲथलिट श्री. स्वप्निल कुसाळे को २ करोड़ रुपये और पॅरीस पॅरा ऑलिम्पिक २०२४ में पदक विजेता श्री. सचिन खिलारी को ३ करोड़ रुपये नक़द पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।

५४. मेरी सरकार ने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए राज्य में चलता-फिरता न्यायसहायक वाहन परियोजना योजनाबद्ध की है। सरकार ने, सायबर अपराधों की चुनौतियों का सामना करने के लिए, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाला, पुणे में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ "डिजीटल न्यायसहायक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र" की स्थापना की है।

५५. किसानों को विकल्प ईंधन ोात के रूप में बांस की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करके हवामान बदल का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यावरण तथा शाश्वत विकास कृती दल का गठन किया है। संपूर्ण राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए हरित महाराष्ट्र कार्यक्रम की घोषणा की है।

५६. मेरी सरकार ने, बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा आंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर, नागपुर में आफ्रिकन सवारी परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए ५१७ करोड़ रुपयों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

५७. मेरी सरकार ने, सतारा जिले के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित स्थानों का एकीकृत पर्यटन विकास, सांगली जिले में छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारकस्थल, चंद्रपूर जिले में विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, सोलापूर जिले में उज़नी जलाशय एकीकृत पर्यटन विकास और अष्टविनायक गणपती मंदिरों का जिर्णोद्धार करने के लिए ८४० करोड़ रुपयों की विकास योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी है।

५८. सरकार ने, राज्य में पर्यटन क्षेत्रों का महत्त्व बढ़ाने और अगले १० वर्षों में लगभग एक लाख करोड़ रुपयों का निजी निवेश आकर्षित करने के लिए "महाराष्ट्र पर्यटन नीति, २०२४" की घोषणा की है। इससे राज्य में ५० शाश्वत विशेष पर्यटन स्थल विकसित होंगे। इससे पर्यटन क्षेत्र में लगभग १८ लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

५९. मेरी सरकार ने, प्रसार भारती के सहयोग से भारत सरकार के ओटीटी इस इंटरनेट आधार पर महाराष्ट्र के पारंपरिक व ोद्योग पर आधारित ५ भागों की मालिका शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। इससे पारंपरिक व ोद्योग और उसकी समृद्ध विरासत को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी।

६०. मेरी सरकार ने, सन् २०२४-२५ में हिंगोली, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, यवतमाल, धाराशिव, नागपुर, वर्धा और ठाणे जिलो में १५ नवीन न्यायालयों की स्थापना की हैं।

६१. मेरी सरकार ने, 'न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास' इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत् न्यायालय भवनों और न्यायाधिशों के लिए आवास स्थानों के संनिर्माण के लिए ७४२ करोड़ रुपयों की लागत से ४४ परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

६२. मेरी सरकार, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मा. उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में महाराष्ट्र की ठोस भुमिका निरंतर रख रही है। महाराष्ट्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में रहनेवाले मराठी भाषी लोगों के लाभ के लिए शैक्षणिक, चिकित्सा और विभिन्न योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन कर रही है।

सम्मानीय सदस्यों, मेरी सरकार राज्य के लोगों को एक स्वच्छ, पारदर्शी, जिम्मेवार और परिणामोन्मुखी प्रशासन देगी। मुझे विश्वास है कि, दोनों सदनों के सभी सदस्य, इसमें सरकार को अपना पूरा सहयोग और समर्थन देंगे तथा मार्गदर्शन करेंगे।

मैं फिर से एक बार, आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिंद! जय महाराष्ट्र!!